आज यहा कह रहे हैं कि आडवाणी जी और लीडर्स आपसे मिलें तब आप इस बारे में कहेंगे ।

MR. CHAIRMAN : You have already told whatever you wanted to tell and you never lost any opportunity to tell what you wanted to tell and we have heard you completely and we will decide it immediately.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, सुनने और सुनकर उसके मुताबिक काम करना ये दो चीजे हैं ।

MR. CHAIRMAN : No. Hearing and acting will be simultaneous and you need not worry about that. Now, let us take up the next item.

REFERENCE TO ALLEGED DAMAGE TO STATUE OF MAHATMA GANDHI WHICH WAS TO BE ERECTED AT INDIA GATE

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, एक और निवेदन करना चाहता हूं । आपके रहते, आप पुरानी परम्परा के है, कल यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति इंडिया गेट पर लगाने के लिये सैंकड़ों जवान जा रहे थे । उनके हाथ से राष्ट्रपिता की मूर्ति छीनकर टुकड़े टुकड़े कर दी गई । यह राष्ट्रपिता की मूर्ति मैं लाया हूं थाने पर जाकर । 12 बजे रात तक उन लोगों को थाने पर रोका गया, उनको खाना नही दिया गया । बहुत परेशानी हुई । यह स्वतंत्र राष्ट्र है । इसके हम नागरिक हैं । तीन मर्तबा इस सदन की कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया है कि इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की जाए । यह मूर्ति मैं आपको दिखा रहा हूं । आपकी आज्ञा से यहां पर रख रहा हूं ।

MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR THE PRESENTATION OF THE REPORT OF THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE PLANTATIONS LABOUR (AMENDMENT) BILL, 1973

SHRI N. R. CHOUDHURY (Assam) : Sir, I beg to move the following motion :

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Plantations Labour (Amendment) Bill, 1973, be further extended up to the first day of the last week of the Ninety-first Session of the Rajya Sabha."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR THE PRESENTATION OF THE REPORT OF THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL, 1973

SHRI MANUBHAI SHAH (Gujarat) : Sir, I beg to move the following motion :

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 1973, be further extended up to the last day of the Ninety-third (Monsoon) Session of the Rajya Sabha."

The question was proposed.

SHRI N.G. GORAY (Maharashtra) : Sir, when more time is asked for, it is not our intention to grudge it. But some explanation should be given why so much time is required.

MR. CHAIRMAN : I think it has already been circulated to all the members. Perhaps the hon. Member might not have got a copy of the circular.

श्री देवराव पाटिल (महाराष्ट्र): यह प्रस्ताव जो आया है संयुक्त समिति के टाइम बढ़ाने के बारे में तो मैं जानना चाहूगा कि इसके टाइम बढ़ाने के क्या कारण है, इतना टाइम क्यो बढ़वाया जा रहा है ?

MR. CHAIRMAN : Perhaps the hon. Member did not hear me. Already, a circular has been issued and the explanation has been given. He may look into it.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैं चाहूंगा कि आप खुद एक कमेटी बैठा दें जो यह विचार करे कि राज्य सभा का रहना राष्ट्रहित में जरूरी है या नही ? क्योकि हम देखते हैं कि जब राज्य सभा जन हित का काम नही कर रही है तो इसमें पैसा क्यो खर्च किया जाये । इसमें राष्ट्र का निजी अपव्यय हो रहा है । जो लोग कमेटियों में रहते है वे रात को डिनर खाते हैं और दिन भर यह सोचते रहते है कि पूंजीपतियों से किस तरह से पैसा आए । मैं चाहूंगा . . .

SHRI N. R. CHOUDHURY (Assam) : He is also a member of the Committee.

श्री राजनारायण : मेरा यह निवेदन है अब राष्ट्र चाहता है इसको जाने कि राज्य सभा की आवश्यकता है या नही, इस पर जो अपव्यय हो रहा है इसके लिए एक कमेटी बैठा दी जाये ?

MR. CHAIRMAN : I will call it. You will be the first person to be invited.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : यह एक आम रिवाज बन गया है कि जितनी यह कमेटियां बनती हैं बराबर अपना टाईम बढवाती रहती हैं। जिन कमेटियों को बने 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए है वे भी बराबर टाईम बढ़ाने की मांग कर रही हैं तो मै चाहूंगी कि कोई टाईम लिमिट होना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर (उत्तर प्रदेश) मेरा यह निवेदन है कि मै इस कमेटी की कार्रवाई के बारे में नही जानता लेकिन धीरे धीरे हम लोगों की यह आदत होती जा रही है कि संसद की जितनी समितियां बनती है वे अपना काम ठीक ढंग से नही करती है। मैं बिना किसी मंशा के चुनौती देते हुए यह कहना चाहूगा कि राजनारायण जी बहुत बाते गलत भी कहते हैं लेकिन यह बात वह सही कर रहे है। यह जो अपव्यय हो रहा है इसको हमें रोकना चाहिए। हम देखते है जब कोई कमेटी बन जाती है तो उसके टाइम बढ़ाने के लिये यह कहा जाता है कि हमें गवाहों को बुलाना है। इतने गवाहों को बुलाया जाता है और जब कुछ और गवाहों को बुलाया जाना है तो क्यों नही जब पार्लियामेंट चल रही होती है उस वक्त बुलाते। मै भी कई समितियों मे रहा हूं और यह रहा है कि जब पार्लियमेंट चल रही होती है उस वक्त समितियां मिली हैं। मेरी समझ में नही आता कि जब ससद का सत्रावसान हो जाता है तब क्यों कमेटियां मिलती है? यह समितियां केवल भत्ता लेने, सारे देश का भ्रमण करने का एक साधन बन गई है। आपको इस पर एक कडा रुख अपनाना चाहिए क्योकि इससे न केवल संसद का काम अवरुद्ध होता है बल्कि लोगो के मन मे इन समितियो के प्रति मर्यादा घटती है। मै चाहूंगा इसकी ओर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए।

SHRI N.R. CHOUDHURY : Shri Goray Ji and Shri Rajnarain Ji raised certain points. I have also been working in some House committees. My humble submission to Shri Goray Ji and Shri Rajnarain Ji will be that they should kindly ask the Members belonging to their parties who sit on these committees, to act in such a manner so that we need not come here praying for extension of time.

SHRI N.G. GORAY : I have not blamed any Member of any party.

SHRI N. R. CHOUDHURY : Sir, as Shri Chandra Shekhar said, I have also seen that it is not the ruling party which is responsible for all these things.

SHRI RABI RAY (Orissa) : Nobody said that.

SHRI N.R. CHOUDHURY : So, it will be better if all the political parties and the opposition parties direct their Members so that they act in such a way that we need not come before the House for extension.

श्री राजनारायण : इसमें पार्टी के सदस्यों का सवाल नही है। आप सदन के सदस्यो की एक कमेटी बनाते है और आपके सचिवालय के कोई आफिसर उसके सचिव होते हैं। अगर आपका सचिवालय हमें लिखकर भेज दे कि अपनी पार्टी के सदस्यो को बदल दीजिये, तो हम बदल देंगे। यह बात समझ में नही आती कि आपकी रूल्स कमेटी भी देश भर का भ्रमण कर रही है। यह क्या मजाक है? रूल्स कमेटी को बाहर जाने की क्या जरूरत है?

SHRI SALIL KUMAR GANGULI (West-Bengal) : The Congress Party is in majority in every committee and the quorum cannot be observed due to their absence. They should not blame others. They should blame themselves. It is their responsibility.

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली) : सभापति जी, मैं समझता हूं कि इस मामले में दलीय राजनीति को न लाया जाये तो उचित होगा। किसी मेम्बर ने किसी पर आरोप नही लगाया है। सरकारी पक्ष पर भी कोई आरोप नही लगाया गया है और विरोधी पक्ष पर भी कोई आरोप नही लगाया गया है। लेकिन यह बात ठीक है कि यह धारणा बाहर भी बढ़ती जा रही है कि संसद के सदस्य समितियो का उपयोग या तो भत्ता लेने की दृष्टि से करते है या भारत भ्रमण की दृष्टि मे करते है। यह स्थिति ठीक नही है और इसका हम सब पर प्रभाव पड़ता है और हमारी प्रतिष्ठा घटती है। यह ठीक है कि किसी समिति का समय बढ़ाया जाये इसमे कोई दो मत नही है क्योंकि मुझे इस बात का पता नही है कि इस समिति का कितना काम बाकी है, इस लिये इस विशेष प्रस्ताव के बारे मे मेरा कोई विरोध नही है।

श्री एन० आर० चौधरी : इसमें जनसंघ के भी दो मेम्बर है।

श्री लाल आडवाणी : मेरा कहना यह है कि जब एक प्रस्ताव सामने आया है तो स्वाभाविक रूप से अनेक सदस्यो के मन मे यह बात आई कि अनेक बार ऐसे प्रस्ताव आते रहते है और समितियो का समय बढाया जाता है। इस लिए मै समझता हूं कि उचित यह होगा कि अगर सारे सदन के सदस्यो की यह राय हो तो आप स्वयं इस मामले में लोक सभा के स्पीकर महोदय से भी राय कर ले क्योकि इसमें दोनो सदनो के सदस्य इनवोल्व होते है और कोई तरीका निकाल ले।

SHRI MANUBHAI SHAH : Sir, my committee has worked only for 11 months so far. This is the first time I am coming for extension. The Members of the Opposition are fully cooperating. I have got no complaint

[Shri Manubhai Shah]

on behalf of either this party or the opposition parties. We are not going to meet outside Delhi. The Bill is of an important nature and so many legal issues are involved. We have asked for an extension of six months which is absolutely reasonable. Therefore, I request that the extension be granted.

MR. CHAIRMAN : On the basis of the little experience I have got during the last two sessions, I can say that some Members want to go to some places. This is one of the reasons for delay in the submission of reports. If the House agrees, I will use my discretion and not allow the committees to visit many places. Then it will be in order

श्री राजनारायण : देश में ही नहीं विदेश में भी मत जाने दीजिए ।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 1973, be further extended up to the last day of the Ninety-third (Monsoon) Session of the Rajya Sabha."

The motion was adopted

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

MOTION REGARDING APPOINTMENT OF A MEMBER OF THE RAJYA SABHA TO THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1974

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. (SMT.) SAROJINI MAHISHI) : Sir, I beg to move :

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint a member of the Rajya Sabha to the Joint Committee of the Houses on the Code of Civil Procedure (Amendment) Bill 1974 in the vacancy caused by the resignation of Shri Bipinpal Das and resolves that Shri Mohammad Usman Arif be appointed to the said Joint Committee to fill the vacancy."

The question was put and the motion was adopted.

REFERENCE TO ACTIVITIES OF MIZO NATIONAL FRONT

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : Sir, in today's 'Statesman', on the front page, there is a story titled, "Mizo Rebels' Warning to Non-tribals." Sir, this warning has been given by the Mizo National Front to the Vais people of Mizoram. These Vais people are the non-tribal people of Mizoram. The warning is, "quit the State before January." According to the newspaper report, Sir, this warning is aimed at government officials in particular. In the 'Statesman' there is also a news item which says that there are elements in Mizoram which want to make this issue an international issue. Sir, this anti-Vais campaign is going on for a long time. I have been reading about it for quite some time. But nothing seems to have been done about it. In particular, the Mizo National Front has capitalized on the anti-Vais sentiment on two grounds. According to the report, Sir, recently, a Minister of Mizoram was humiliated by Central Government officials there. A local official had also been similarly humiliated by a search of his house when his belongings were thrown out. Sir, I would like to know the truth. The second ground is this. The Mizoram Trading (Regulation) Act for Non-tribals which was passed recently by the Assembly in a very unorthodox manner has apparently not reflected the aspirations of the people of that State. Now, these two aspects have been brought out by the Mizo National Front, and the public sentiment is being exploited. The question is: Why is it that the Mizo National Front is able to exploit the public sentiment? Sir, looking at some of the reports, I have, it seems that there are two reasons for this. Number one is, the Lieutenant-Governor in Mizoram acts entirely in collusion with the Chief Secretary of Mizoram and bypasses the Chief Minister, Mr. Chhunga, on major issues. For example, on the Trading Act, the Chief Minister was not taken into confidence. May be, the Chief Minister has different views. But the fact is that he is the Chief Minister. And the Lieutenant-Governor by passing the Chief Minister, acting in concert with the Chief Secretary and then turning up in Delhi and drafting and redrafting the Bill according to his choice is bound to create a feeling that somehow the people of Mizoram are not fit to determine the day-to-day working of their State. Sir, the second aspect is the so called inner-line permit system which was originally passed in